नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 121
दि. 03.02.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

बीएमसी के गलियारों में बदला सत्ता का रंग, पहली बार 'भाजपा राज' की गूंज

(जीएनएस)। मुंबई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के इतिहास में सोमवार का दिन एक नई राजनीतिक इबारत लिख गया। दशकों तक शिवसेना के प्रभाव और वर्चस्व के लिए पहचानी जाने वाली बीएमसी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और सत्ता की धुरी बनकर सामने आई। 2026 के नगर निकाय चुनावों में ऐतिहासिक जीत के बाद जब नवनिर्वाचित पार्षद पहली आधिकारिक बैठक के लिए पालिका मुख्यालय पहुंचे, तो माहौल पूरी तरह बदला-बदला नजर आया। मुख्यालय के गलियारों में 'जय श्री राम' के नारों की गूंज, भगवा रंग की मौजूदगी और आत्मविश्वास से लबरेज चेहरों ने यह संकेत दे दिया कि मुंबई की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है।

बीजेपी के 89 पार्षद मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम के नेतृत्व में संगठित तरीके से मुख्यालय पहुंचे। यह दृश्य सिर्फ संख्या का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उस बदलाव का प्रतीक था, जिसका इंतजार बीजेपी लंबे समय से कर रही थी। 227 सदस्यीय सदन में बीजेपी अकेले सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई है। शिवसेना (शिंदे गुट) के 29 पार्षद और अजित पवार गुट के 3 पार्षदों के समर्थन से महायुति का आंकड़ा 121 तक पहुंच गया है, जो बहुमत के लिए जरूरी 114 के आंकड़े से काफी ऊपर है। इस स्पष्ट बहुमत ने सत्ता को लेकर किसी भी तरह की अनिश्चितता को लगभग खत्म कर दिया है।

पालिका मुख्यालय में सोमवार को जो दृश्य देखने को मिला, उसने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का मंच भी था। बीजेपी और शिंदे गुट दोनों ही अपने-अपने स्तर पर यह जताने में लगे थे कि बीएमसी में उनकी भूमिका निर्णायक होगी। गलियारों में गूंजते नारों, समर्थकों की भीड़ और नेताओं की सक्रियता ने माहौल को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया। लंबे समय तक शिवसेना (यूबीटी) के नियंत्रण में रही बीएमसी में सत्ता का यह परिवर्तन राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है।

इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा मेयर पद को लेकर है। लॉटरी प्रक्रिया के तहत इस बार मुंबई के मेयर का पद 'सामान्य वर्ग की महिला' के लिए आरक्षित हुआ है। इस आरक्षण ने बीजेपी के भीतर दावेदारों की धड़कनें तेज कर दी हैं। पार्टी के अंदर

अनुभवी और जमीनी पकड़ वाले चेहरों को आगे लाने पर मंथन चल रहा है। माहिम-दादर जैसे मजबूत क्षेत्र से जीत दर्ज करने वाली शीतल का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी मानी जाने वाली शीतल को प्रखर वक्ता और मराठी मतदाताओं में अच्छी पकड़ रखने वाली नेता के रूप में देखा जाता है। वहीं घाटकोपर से दूसरी बार पार्षद बनीं रितु तावड़े भी मजबूत दावेदार के रूप में उभरी हैं, जिनकी पहचान एक प्रशासनिक समझ रखने वाली और जमीनी स्तर पर सक्रिय नेता की है। इनके अलावा अलका केरकर और तेजस्वी घोषालकर जैसे नाम भी पार्टी के भीतर चर्चा में हैं, जिससे यह साफ है कि मेयर पद की रेस बेहद रोचक होने वाली है।

सत्ता गठन की प्रक्रिया के तहत एक अहम फैसला यह भी रहा कि बीजेपी और शिवसेना (शिंदे गुट) ने संयुक्त गुट पंजीकरण के बजाय अलग-अलग गुट बनाने का निर्णय लिया। चुनाव परिणाम आए हुए पंद्रह दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद गुट पंजीकरण की प्रक्रिया रुकी हुई थी। संयुक्त या स्वतंत्र गुट पंजीकरण को लेकर दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। इसी बीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद घोषित सरकारी शोक के चलते प्रक्रिया और आगे खिसक गई। अंततः सोमवार को यह तय हुआ कि दोनों दल स्वतंत्र रूप से गुट पंजीकरण करेंगे, हालांकि महायुति के रूप में सत्ता में साथ रहेंगे।

इस फैसले के साथ ही गुट नेताओं की घोषणा भी कर दी गई। बोरीवली के वार्ड 7 से जीतने वाले गणेश खनकर को बीजेपी का गुट नेता बनाया गया है। गणेश खनकर को संगठन और प्रशासन दोनों का अनुभव रखने वाला नेता माना जाता है और पार्टी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में सदन के भीतर बीजेपी की रणनीति मजबूत रहेगी। शिवसेना (शिंदे गुट) की कमान वडाला के अनुभवी पार्षद अमेय घोले को सौंपी गई है। विपक्षी खेमे में शिवसेना (यूबीटी) ने पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर पर ही भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा गुट नेता की जिम्मेदारी दी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि विपक्ष भी आक्रामक भूमिका निभाने की तैयारी में है।

राजनीतिक समीकरणों को और मजबूत करते हुए दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के तीन नगरसेवकों ने शिवसेना (शिंदे गुट) के साथ गुट पंजीकरण करने का फैसला किया है। इससे शिंदे गुट की संख्या 29 से बढ़कर 32 हो जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव सोमवार को पालिका मुख्यालय में पारित किया गया। इस मौके पर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम और मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा की मौजूदगी ने यह संदेश दिया कि महायुति अपने आंकड़ों और रणनीति को लेकर पूरी तरह सतर्क और संगठित है।

अब सबकी नजरें 6 फरवरी पर टिकी हैं, जब मुंबई को नया मेयर मिलने की संभावना है। कोंकण भवन में सभी दलों ने पार्षदों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। महायुति के भीतर मेयर और डिप्टी मेयर के साथ-साथ स्थायी समिति, सुधार समिति और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक समितियों के बंटवारे को लेकर गहन मंथन चल रहा है। सूत्रों के अनुसार, बीजेपी मेयर पद अपने पास रखने की तैयारी में है, जबकि डिप्टी मेयर का पद शिवसेना (शिंदे गुट) को दिया जा सकता है। इससे दोनों दलों के बीच सत्ता संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है।

बीएमसी में सत्ता परिवर्तन सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि मुंबई की राजनीति की दिशा और दशा को प्रभावित करने वाला कदम माना जा रहा है। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई की नगर सरकार पर नियंत्रण का मतलब है अरबों रुपये के बजट, बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स और शहर के विकास की दिशा तय करने की शक्ति। ऐसे में बीजेपी के लिए यह जीत प्रतीकात्मक से कहीं ज्यादा रणनीतिक महत्व रखती है।

सोमवार को बीएमसी मुख्यालय में जोश, उत्साह और शक्ति प्रदर्शन के बीच यह साफ हो गया कि आने वाले दिनों में मुंबई की राजनीति और भी गर्म रहने वाली है। सत्ता पक्ष जहां अपने नए 'भाजपा राज' को मजबूती से स्थापित करने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष भी हर कदम पर सरकार को घेरने के मूड में दिख रहा है। 6 फरवरी को नए मेयर के चयन के साथ ही यह तस्वीर और साफ हो जाएगी कि मुंबई की नगर राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी, लेकिन इतना तय है कि बीएमसी अब एक नए राजनीतिक अध्याय की ओर बढ़ चुकी है।

कर्नाटक में सत्ता की खींचतान से प्रशासन पंगु, कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और विफलता के गंभीर आरोप

(जीएनएस)। बेंगलुरु। कर्नाटक की राजनीति में सोमवार को उस समय सियासी तापमान और बढ़ गया, जब विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार को भ्रष्टाचार में डूबी हुई बताते हुए दावा किया कि राज्य का प्रशासन अब "कोमा की स्थिति" में पहुंच चुका है। अशोक ने आरोप लगाया कि राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने जनता के सामने एक चमकदार तस्वीर पेश करने की कोशिश की, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अशोक ने कहा कि कांग्रेस सरकार का पूरा कार्यकाल अब तक आरोपों, विवादों और आंतरिक कलह से घिरा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की प्राथमिकता जनकल्याण नहीं, बल्कि सत्ता के भीतर चल रहा संघर्ष और राजनीतिक संतुलन साधना बन गई है। अशोक के अनुसार, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच चल रही खींचतान ने शासन व्यवस्था को गंभीर रूप से कमजोर किया है, जिसका सीधा असर प्रशासनिक फैसलों और विकास कार्यों पर पड़ रहा है।

भाजपा नेता ने कहा कि राज्य में अफसरशाही असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि यह स्पष्ट

नहीं है कि अंतिम निर्णय कौन ले रहा है। सत्ता के दो केंद्रों के कारण नीतिगत फैसले या तो लटक जाते हैं या फिर देर से लागू होते हैं। अशोक का आरोप था कि इस सत्ता संघर्ष ने न केवल प्रशासन को पंगु किया है, बल्कि जनता के विश्वास को भी गहरी चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि किसान, युवा, व्यापारी और आम नागरिक सरकार की नीतियों से परेशान हैं, लेकिन सरकार अपनी आंतरिक राजनीति में उलझी हुई है।

आर. अशोक ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले पारदर्शिता और ईमानदार शासन का वादा किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके उलट हालात दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं और सरकार उन पर प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रही है। अशोक ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में जिन उपलब्धियों का जिक्र किया गया, वे केवल कागजों तक सीमित हैं और उनका जनता के जीवन पर कोई ठोस असर नहीं दिखता।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने और पार्टी आलाकमान को खुश रखने के लिए राज्य के हितों से समझौता कर रही है। अशोक के अनुसार, कई अहम फैसले कर्नाटक की जरूरतों को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठे नेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार लिए जा रहे हैं। इससे राज्य के गौरव और स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने जिस उम्मीद से कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी, वह उम्मीद अब टूटती नजर आ रही है।

विपक्ष के नेता ने यह भी कहा कि सरकार की नीतियों और आंतरिक विवादों का असर विकास परियोजनाओं पर साफ दिख रहा है। कई योजनाएं या तो धीमी गति से चल रही हैं या फिर अधर में लटकी हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और निवेश के मोर्चे पर राज्य पिछड़ता जा रहा है। अशोक ने सरकार से सवाल किया कि यदि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर प्रशासनिक मशीनरी में असंतोष और अव्यवस्था क्यों दिखाई दे रही है। कांग्रेस सरकार की ओर से हालांकि इन आरोपों को राजनीतिक बताया जा रहा है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं का कहना है कि विपक्ष जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है। उनका तर्क है कि सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं और विकास कार्यों पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। बावजूद इसके, विधानसभा में अशोक के तीखे हमले ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में कर्नाटक की राजनीति में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होने वाला है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता के भीतर कथित खींचतान और विपक्ष के लगातार हमले कांग्रेस सरकार के लिए चुनौती बन सकते हैं। यदि सरकार इन आरोपों का ठोस जवाब देने और प्रशासनिक स्थिरता का भरोसा दिलाने में सफल नहीं होती, तो इसका असर आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल, आर. अशोक के बयान ने कर्नाटक की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है और यह साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलता और सत्ता संघर्ष के मुद्दे आने वाले सत्रों में भी सदन के केंद्र में रहने वाले हैं।

मुंडवा जमीन सौदे में नया मोड़, चार्जशीट से पार्थ पवार बाहर, सियासी बहस फिर गरमाई

(जीएनएस)। पुणे। पुणे जिले के बहुचर्चित मुंडवा जमीन घोटाले में सोमवार को उस समय नया मोड़ आ गया, जब खड़क क्राइम ब्रांच ने अदालत में 1886 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पुत्र पार्थ पवार और उनके सहयोगी दिग्विजय पाटिल का नाम शामिल नहीं किया गया है। पुलिस ने जांच के आधार पर केवल शीतल तेजवानी को मुख्य आरोपी के रूप में नामजद किया है। इस घटनाक्रम के बाद जहां पार्थ पवार को बड़ी कानूनी राहत मिली है, वहीं महाराष्ट्र की राजनीति और सामाजिक हलकों में एक बार फिर तीखी बहस छिड़ गई है।

क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, अब तक की जांच में पार्थ पवार या दिग्विजय पाटिल की प्रत्यक्ष भूमिका से जुड़े कोई ठोस और प्रमाणिक साक्ष्य सामने नहीं आए। पुलिस का कहना है कि जमीन सौदे से संबंधित दस्तावेजों, बैंक लेन-देन, राजस्व रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों की गहन पड़ताल की गई, लेकिन इन दोनों के खिलाफ आरोप तय करने लायक सामग्री नहीं मिली। इसी आधार पर चार्जशीट में केवल शीतल तेजवानी को आरोपी बनाया गया है। पुलिस का यह

भी कहना है कि यदि भविष्य में कोई नया तथ्य सामने आता है, तो जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है।

मुंडवा जमीन घोटाला पिछले कई महीनों से चर्चा में रहा है। मामला पुणे के मुंडवा इलाके में स्थित उस जमीन से जुड़ा है, जो विशेष प्रयोजन और एक खास वर्ग के लिए आरक्षित बताई जाती है। आरोप है कि इस जमीन का सौदा नियमों को ताक पर रखकर बेहद कम कीमत पर किया गया। शिकायतकर्ताओं का दावा रहा है कि जमीन का बाजार मूल्य कहीं अधिक था, लेकिन राजनीतिक प्रभाव और प्रशासनिक मिलीभगत के चलते इसे औने-पौने दाम पर बेच दिया गया। यही नहीं, राजस्व विभाग से जुड़े कुछ नियमों को नजरअंदाज करते हुए भारी-भरकम शुल्क में भी छूट दी गई।

इस पूरे प्रकरण को सामने लाने में समाजसेविका अंजली दमानिया की अहम भूमिका रही है। उन्होंने इस सौदे को लेकर न केवल शिकायत दर्ज कराई, बल्कि लगातार सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर सवाल उठाती रहीं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद दमानिया ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे "न्याय का मजाक" करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या महाराष्ट्र में कानून केवल आम लोगों के लिए ही सख्त है और प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों के लिए अलग पैमाना अपनाया जाता है। दमानिया का कहना है कि जिस सौदे में राजनीतिक प्रभाव की बात शुरू से होती रही, वहां केवल एक व्यक्ति को आरोपी बनाना कई संदेह पैदा करता है।

दमानिया ने यह भी कहा कि चार्जशीट का आकार भले ही 1886 पन्नों का हो, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इसमें सभी पहलुओं को ईमानदारी से शामिल किया गया है। उनके मुताबिक, पार्थ पवार और दिग्विजय पाटिल की भूमिका को लेकर जो आरोप सामने आए थे, उनकी गहराई से जांच होनी चाहिए थी। उन्होंने संकेत दिए कि वे इस मामले को लेकर आगे कानूनी और सामाजिक स्तर पर लड़ाई जारी रखेंगी।

दूसरी ओर, पार्थ पवार के समर्थकों और एनसीपी खेमे में इस चार्जशीट को न्यायिक प्रक्रिया की जीत के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि यह साबित हो गया है कि राजनीतिक आरोपों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उनका तर्क है कि लंबे समय से पार्थ पवार का नाम इस मामले से जोड़ा जा रहा था, लेकिन जांच एजेंसियों को उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ऐसे में चार्जशीट से उनका नाम बाहर रहना स्वाभाविक है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल एक जमीन सौदे तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता, प्रभाव और पारदर्शिता के सवालों से भी जुड़ा हुआ है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार पहले से ही कई बार राजनीतिक विवादों के केंद्र में रहे हैं, ऐसे में उनके बेटे का नाम इस घोटाले से जुड़ना विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन गया था। अब चार्जशीट में नाम न होने से एनसीपी को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं।

समीर वानखेड़े प्रकरण में हाईकोर्ट का अहम मोड़, केन्द्र की याचिका पर फैसला सुरक्षित

(जीएनएस)। नई दिल्ली। वर्ष 2021 के चर्चित कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग कांड से जुड़े आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक अहम कदम उठाते हुए केन्द्र सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह याचिका उस आदेश को चुनौती देने से जुड़ी है, जिसमें केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) ने वानखेड़े के खिलाफ प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट की इस सुनवाई को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह मामला न सिर्फ एक वरिष्ठ अधिकारी के करियर से जुड़ा है, बल्कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सीमाओं पर भी सवाल उठते हैं।

न्यायमूर्ति अनिल क्षेतरपाल और न्यायमूर्ति अमित महाजन की खंडपीठ ने केन्द्र सरकार और समीर वानखेड़े, दोनों पक्षों के वकीलों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद निर्णय को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। अदालत ने संकेत दिया कि मामले में उठाए गए कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं पर गहन विचार की आवश्यकता है, जिसके बाद ही अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। दरअसल, यह मामला केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 19 जनवरी के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें सीएटी ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा 18 अगस्त 2025 को समीर वानखेड़े को जारी किए गए आरोप ज्ञापन को रद्द कर दिया था। सीएटी ने अपने आदेश में कहा था कि वानखेड़े के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होती है और रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों के आधार पर इसे टिकाऊ नहीं माना जा सकता। इसी आदेश को केन्द्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

समीर वानखेड़े, जो 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं, वर्ष 2021 में मुंबई स्थित नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) में तैनात थे। उसी दौरान कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग कांड सामने आया था, जिसने देशभर में व्यापक चर्चा और राजनीतिक बहस को जन्म दिया था। इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद वानखेड़े सुर्खियों में आ गए थे। बाद में उन पर आरोप लगे कि उन्होंने आर्यन खान को मामले में फंसाने की धमकी देकर कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की मांग की थी। हालांकि वानखेड़े ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था और खुद को एक साजिश का शिकार बताया था।

सीबीआईसी की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि वानखेड़े ने एनसीबी के कानूनी विभाग से जांच से जुड़ी गोपनीय जानकारी मांगी और यह आश्वासन लेने की कोशिश की कि जांच उनकी इच्छा के अनुसार चलेगी। इसी आधार पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। वानखेड़े ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए सीएटी का दरवाजा खटखटाया था, जहां उन्हें राहत मिली और आरोप ज्ञापन को रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट में केन्द्र सरकार की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि सीएटी का यह निष्कर्ष कि अनुशासनात्मक कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण थी, रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों के आलोक में सही नहीं है। केन्द्र का कहना था कि एक वरिष्ठ अधिकारी के आचरण से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच करना प्रशासन का अधिकार और कर्तव्य है, और इस स्तर पर कार्रवाई को रद्द करना अनुचित है। वहीं समीर वानखेड़े की ओर से दलील दी गई कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई तथ्यों से परे और पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, जिसे सीएटी ने सही ढंग से पहचाना और रद्द किया।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मामला कई संवेदनशील पहलुओं से जुड़ा है और इसका प्रभाव प्रशासनिक कानून तथा अनुशासनात्मक प्रक्रिया की व्याख्या पर पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रखने का निर्णय लिया।

बारामती की धरती पर स्मृति में अमर होंगे अजित पवार

(जीएनएस)। बारामती। महाराष्ट्र की राजनीति में गहरी छाप छोड़ने वाले दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की स्मृतियों को सहेजने की दिशा में एक भावनात्मक और ऐतिहासिक पहल की जा रही है। बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान परिसर में उनका स्मारक बनाए जाने की योजना सामने आई है। यह वही परिसर है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था और जहां आज भी उनके समर्थकों और शुभचिंतकों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इस निर्णय को बारामती ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक प्रतीकात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अजित पवार का राजनीतिक और सामाजिक जीवन इसी क्षेत्र से गहराई से जुड़ा रहा। पवार परिवार के करीबी और विश्वासपात्र किरण गुर्जर ने इस योजना की जानकारी साझा करते हुए बताया कि स्मारक निर्माण को लेकर परिवार और विद्या प्रतिष्ठान के न्यासियों के बीच जल्द ही विस्तृत चर्चा होगी। स्मारक का स्वरूप, उसका डिजाइन और उसमें समाहित किए जाने वाले विचार अजित पवार के व्यक्तित्व, उनके राजनीतिक संघर्ष और बारामती के प्रति उनके समर्पण को दर्शाएंगे। गुर्जर के अनुसार, यह स्मारक केवल एक संरचना नहीं होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। अजित पवार का निधन 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती हवाई पट्टी के पास हुए एक विमान हादसे में हुआ था। इस हादसे में उनके साथ चार अन्य लोगों की भी जान चली गई थी। इस दुखद घटना ने न सिर्फ पवार परिवार, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति और जनता को गहरे शोक में डुबो दिया था। अजित पवार की आकस्मिक मृत्यु ने एक ऐसे नेता को छीन लिया, जो अपने सख्त फैसलों, प्रशासनिक पकड़ और जमीनी राजनीति के लिए जाने जाते थे। बारामती अजित पवार के जीवन और कर्मभूमि का केंद्र रहा है। यही वह क्षेत्र है, जहां से उन्होंने राजनीति की ऊंचाइयों तक का सफर तय किया और जहां के विकास के लिए उन्होंने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को आकार दिया। सिंचाई, शिक्षा, सहकारिता और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उनके प्रयासों ने बारामती को एक अलग पहचान दी। विद्या प्रतिष्ठान स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में पवार परिवार की दूरदृष्टि का प्रतीक है और उसी परिसर में स्मारक का निर्माण होना उनके जीवन दर्शन से जुड़ा एक भावनात्मक निर्णय माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह स्मारक न केवल अजित पवार के योगदान को सम्मान देगा, बल्कि बारामती की पहचान को भी और मजबूत करेगा। यह स्थान भविष्य में उनके समर्थकों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए एक ऐसा केंद्र बन सकता है, जहां वे उनके विचारों, संघर्षों और उपलब्धियों को करीब से समझ सकेंगे। स्थानीय लोगों के बीच भी इस प्रस्ताव को लेकर सकारात्मक भावनाएं देखी जा रही हैं, क्योंकि अजित पवार को बारामती के विकास का मजबूत स्तंभ माना जाता रहा है। पवार परिवार से जुड़े सूत्रों के अनुसार, स्मारक को भव्य लेकिन सादगीपूर्ण रखने की सोच है, ताकि वह अजित पवार के व्यक्तित्व को सही मायने में प्रतिबिंबित कर सके। उनके जीवन की प्रमुख झलकियां, राजनीतिक सफर और बारामती के लिए किए गए कार्यों को स्मारक के माध्यम से सामने लाने की योजना है। इसके साथ ही, यह स्मारक एक सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है, जहां लोग न केवल श्रद्धांजलि अर्पित करें, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों से भी जुड़ सकें। अजित पवार का नाम महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय तक गूंजता रहा है और उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। विद्या प्रतिष्ठान परिसर में बनने वाला यह स्मारक उस विरासत को स्थायी रूप देने का प्रयास होगा, जो उन्होंने अपने जीवनकाल में बनाई।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

बजट में युवा व चुनावी राज्यों का ध्यान

राजग सरकार द्वारा रविवार को पेश किया गया आम बजट 2026-27 कई मायनों में खास, संकेतक और दूरगामी प्रभाव वाला माना जा रहा है। यह बजट केवल आंकड़ों और घोषणाओं का दस्तावेज नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक दिशा को लेकर अपने इरादे भी स्पष्ट किए हैं। लगातार नौवीं बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का तमिलनाडु की पहचान मानी जाने वाली कांजीवरम साड़ी में संसद पहुंचना एक प्रतीकात्मक संदेश भी था। यह न केवल नारी शक्ति के आत्मविश्वास को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराएं विकास की मुख्यधारा में सम्मान के साथ शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की दिशा और दर्शन को तीन शब्दों—स्किल, स्केल और सस्टेनबिलिटी—में परिभाषित किया। इन तीन शब्दों में सरकार की दीर्घकालिक सोच छिपी हुई है। स्किल का अर्थ है देश के युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित करना, स्केल का मतलब है योजनाओं और उद्योगों को बड़े स्तर पर विस्तार देना, और सस्टेनबिलिटी का संकेत है कि विकास पर्यावरण और संसाधनों के संतुलन के साथ हो। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे विकास और आत्मनिर्भरता का बजट बताते हुए कहा कि यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। वहीं विपक्ष ने हमेशा की तरह आरोप लगाया कि इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं है।

हर बजट के समय आम नागरिक की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलेगा। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा और कहां खर्च बढ़ेगा। इस बार सरकार ने कुछ वस्तुओं को सस्ता करने का ऐलान कर मध्यम वर्ग और गरीब तबके को राहत देने की कोशिश की है। माइक्रोवेव ओवन, सोलर पैनल, चमड़ा उत्पाद और 17 दवाइयों को सस्ता किया जाना उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। खास तौर पर सात दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने का फैसला सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाता है, क्योंकि इन बीमारियों के इलाज का खर्च अक्सर परिवारों को आर्थिक संकट में डाल देता है। दूसरी ओर शराब, सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पादों पर कर बढ़ाने की परंपरा इस बार भी जारी रही। इससे सरकार ने एक ओर जहां राजस्व बढ़ाने की कोशिश की है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य के प्रति सख्त संदेश भी दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में विदेशों में पढ़ रहे छात्रों के लिए भेजे जाने वाले धन पर टीसीएस कम करना एक अहम फैसला है। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जिनके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए हैं। इसके साथ ही विदेश यात्रा पैकेज पर दी गई छूट से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस बजट का एक अहम राजनीतिक पक्ष उन राज्यों से जुड़ा है, जहां आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। दुर्लभ रेयर अर्थ तत्वों पर फोकस करते हुए रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें तमिलनाडु और केरल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी उत्पादों में रेयर अर्थ की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही इन राज्यों के मछुआरों और नारियल उत्पादकों को प्रोत्साहन और छूट देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की गई है। हालांकि बजट के बाद शेयर बाजार की प्रतिक्रिया कुछ खास उत्साहजनक नहीं रही। एसटीटी बढ़ाने के फैसले से निवेशकों में निराशा देखी गई और बाजार में गिरावट दर्ज की गई। यह दिखाता है कि सरकार ने बाजार की अल्पकालिक प्रतिक्रिया की बजाय राजस्व और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दी है। उद्योग जगत के लिए बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लक्ष्य के अनुरूप है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जारी अस्थिरता के बीच यह निवेश भारत के लिए बड़ा अवसर साबित हो सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 'बायोफार्मा शक्ति योजना' के तहत 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य मधुमेह और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की सस्ती और सुलभ दवाइयां उपलब्ध कराना है। यदि यह योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है तो देश के करोड़ों मरीजों को सीधा लाभ मिल सकता है और भारत फार्मा सेक्टर में वैश्विक स्तर पर और मजबूत स्थिति में आ सकता है।

संगठित आतंकवाद वैश्विक शांति के लिए खतरा

> "आतंकवाद का मुखर समर्थन करने वाले देशों के पीछे बड़ी ताकतें रहती हैं, जो उन्हें आर्थिक सहायता और हथियारों की आपूर्ति कर उनकी पीठ थपथपाती हैं।

दुनिया में आतंकवाद अब कोई स्थानीय समस्या नहीं रहा। इसका नियंत्रण भी प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानीय दृष्टिकोण से नहीं हो सकता। आतंकवाद विश्व स्तर पर एक संगठित धंधा बन चुका है। अलग-अलग देशों—चाहे फ़लस्तीन हो या पाकिस्तान—में आतंकवाद का पोषण खुलेआम होता है। फ़लस्तीन में हमास की गतिविधियां और पाकिस्तान में आतंकवादियों के पोषण के अड्डे किसी से छिपे नहीं हैं। आतंकवाद का पोषण भी एक संगठित तरीके से विभिन्न देशों द्वारा किया जाता है, लेकिन जब इस मानवता-विरोधी कारगुज़ारी पर सवाल उठाए जाते हैं, तो वे बड़ी मासूमियत से अपनी संलिप्तता से इनकार कर देते हैं।

भारत के विरुद्ध आतंकवाद का निरंतर पोषण करते हुए भी पाकिस्तान कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता, बल्कि स्वयं को आतंकवाद से पीड़ित बताता रहता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की चाल भी निराली है। पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान को आतंकवाद का शिकार देश बताते हुए उसे आतंक के मुकाबले में अग्रणी करार दे दिया था। आतंकवादी पाकिस्तान में पनाह लिए रहते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादी सूचियों में दुर्दांत आतंकवादियों के नाम गायब हो जाते हैं। आतंकवाद का मुखर समर्थन करने वाले इन देशों के पीछे बड़ी ताकतें रहती हैं, जो उन्हें आर्थिक सहायता और हथियारों की आपूर्ति कर पीठ थपथपाती हैं।

दुनिया भर में आतंकवाद एक संगठित कारोबार के रूप में फैलता जा रहा है। यदि पाकिस्तान के आतंकवाद पर अप्रत्यक्ष रूप से चीन की सहमति है, तो फ़लस्तीन के हमास आतंकियों के पीछे कुछ इस्लामिक देश हैं। लेकिन जो सच है, उसे नज़रअंदाज़ कर आतंक-पोषक देश अपनी मासूमियत जताते हैं। वास्तव में आतंकवाद की शिकार वह साधारण जनता है, जिसके जान-माल और रोज़ी-रोटी पर आतंकियों का कुठाराघात होता है।

पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद के सामने नाटकीय ढंग से आतंकवाद का पोषक होने से इनकार किया। उसने कहा कि केवल सरकारी नीति के अनुसार ही देश में व्यवस्था चलाई जाती है और उसी के तहत शत्रु का मुकाबला किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर भी झूठा ब्योरा प्रस्तुत किया और पहलगाम की निर्मम घटना के दोष से स्वयं को बरी कर लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के सुरक्षा प्रतिनिधि ने खरी-खरी सुनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर झूठा ब्योरा पेश करने को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने ज़ोर देकर कहा कि इस्लामाबाद आतंकवाद को सामान्य घटना के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संयुक्त राष्ट्र के इस सदन में पाकिस्तान आतंकवाद को वैध ठहराने की अपनी ओछी हरकत नहीं कर सकता।

पहलगाम में अप्रैल, 2025 में पाकिस्तानी आतंकियों ने जघन्य हमला कर निर्दोष नागरिकों की हत्या की थी। इस आतंकी घटना के जवाब में और पाकिस्तानी आतंकी अड्डों को नष्ट करने के उद्देश्य से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारत ने पाकिस्तान के भीतर जाकर आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया और पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्रों में भी आतंकी ढांचों को नष्ट किया। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह फिर से आतंकी अड्डों को पुनर्जीवित कर आतंकवाद के पोषण में जुटा हुआ है।

आज संयुक्त राष्ट्र संघ भी अपनी प्रासंगिकता खोता हुआ प्रतीत हो रहा है। वह कहीं भी शांति सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं दिखता। उसके निंदा प्रस्तावों का आतंकियों या उन्हें संरक्षण देने वाले देशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही देश संयुक्त राष्ट्र के मंच पर आकर स्वयं को आतंकवाद से पीड़ित मासूम राष्ट्र बताते हैं। भारतीय प्रतिनिधि ने स्पष्ट कहा कि संयुक्त राष्ट्र केवल बजट की चिंता तक सीमित न रहे, बल्कि संघर्षों से निपटने में अपनी जड़ता और प्रभावहीनता को समाप्त करे। इसी कारण आतंकवादी सिर उठा रहे हैं और अपने षड्यंत्रकारी, आक्रामक रवैये से विश्व को युद्ध की ओर धकेल रहे हैं।

आतंकवाद अब स्थानीय नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और मानवीय मूल्यों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। यह धीरे-धीरे एक संगठित और व्यावसायिक स्वरूप ले रहा है। इस प्रकार आतंकवाद एक घातक वैश्विक बाजार में बदलता जा रहा है, जो विकास के बजाय मृत्यु का संदेश देता है। ऐसे में इससे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी भूमिका और दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। सुरक्षा परिषद को वीटो-आधारित यंत्रचालित ढांचे से बाहर निकलकर पारदर्शिता, सत्य और न्याय पर आधारित प्रभावी मंच बनना चाहिए।

प्रेरणा

इंसान के कर्मों में छिपी हुई जन्नत और दोज़ख़

स्वर्ग और नरक की अवधारणा मानव सभ्यता जितनी ही पुरानी है। अलग-अलग धर्मों, परंपराओं और दर्शन में इनके अलग-अलग रूप मिलते हैं, लेकिन मूल भावना लगभग एक-सी है—अच्छे कर्मों का फल सुख और बुरे कर्मों का परिणाम दुख। अक्सर लोग मानते हैं कि स्वर्ग और नरक मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई जगहें हैं, जहां इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से भेजा जाएगा। लेकिन सूफी परंपरा इस धारणा को एक कदम आगे ले जाकर यह कहती है कि जन्नत और दोज़ख़ कोई दूर की दुनिया नहीं, बल्कि इसी धरती पर, इसी जीवन में इंसान के साथ चलती हैं। एक सूफी संत से जुड़ी कथा इस गहरे सत्य को बहुत सहज ढंग से उजागर करती है।

कहानी की शुरुआत कुछ जिज्ञासु लोगों से होती है, जो एक सूफी संत के पास जाकर पूछते हैं कि जन्नत और दोज़ख़ आखिर क्या होते हैं। वे जानना चाहते थे कि स्वर्ग की खुशहाली कैसी होती है और नरक की यातना किस रूप में मिलती है। सूफी संत ने न तो कोई धार्मिक ग्रंथ खोला और न ही कोई उपदेशात्मक भाषण दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि वे अगले दिन उनके साथ चलें। संत का यह उत्तर सुनकर लोग हैरान तो हुए, लेकिन उत्सुकता के कारण सहमत हो गए।

अगले दिन सूफी संत उन्हें सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति के पास ले गए, जो शिकार करके जीवन यापन करता था। उसके आसपास मारे गए जानवरों के अवशेष पड़े थे। उसका चेहरा कठोर था, आंखों में संवेदना की जगह लालच और निर्दयता दिखाई देती थी। उसके लिए जीवन केवल अपनी भूख, अपने लाभ और अपनी शक्ति का विस्तार था। सूफी संत ने उस दृश्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि यही दोज़ख़ है। जो इंसान दूसरों के जीवन के प्रति संवेदनशील नहीं रहता, जो हिंसा और क्रूरता को अपना स्वभाव बना लेता है, उसके लिए यह दुनिया भी नरक बन जाती है। वह भले ही जीवित हो, लेकिन भीतर से वह जलता रहता है—डर, असंतोष और खालीपन में।

इसके बाद सूफी संत उन लोगों को जंगल के भीतर ले गए, जहां एक फ़क़ीर एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसके पास न धन था, न वैभव, न आराम के साधन। फिर भी उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों में संतोष और मन में सुकून था। वह प्रकृति के बीच रहकर अपनी सीमित जरूरतों में जीवन बिताता था और शेष समय आत्मचिंतन में लगाता था। सूफी संत ने बताया कि यह वह व्यक्ति है जिसने इच्छाओं पर विजय पा ली है। उसने आज के दिखावटी सुखों का त्याग करके भीतर की शांति को चुना है। ऐसा व्यक्ति भले ही बाहर से गरीब दिखे, लेकिन उसके भीतर जन्नत बसी होती है।

अंत में सूफी संत लोगों को एक सामान्य गृहस्थ के घर ले गए। वह कोई संत नहीं था, न ही कोई तपस्वी। वह अपने परिवार के साथ सादगी से जीवन जी रहा था। उसके घर में प्रेम था, आपसी सम्मान था, मेहनत से कमाया गया भोजन था और जरूरतमंदों की सहायता करने की भावना थी। वहां न लालच था, न भय, न ही दिखावे की होड़। सूफी संत ने कहा कि ऐसे लोग ही जीवन की सच्ची जन्नत में रहते हैं। उनके लिए यह धरती भी स्वर्ग है और मरने के बाद भी उन्हें स्वर्ग ही मिलता है।

यह कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आईना है। आज का मनुष्य आधुनिक सुविधाओं से घिरा हुआ है, फिर भी भीतर से अशांत है। अधिक पाने की लालसा, दूसरों से आगे निकलने की होड़ और असुरक्षा की भावना ने उसके मन को बेचैन बना दिया है। धन, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागते-भागते वह यह भूल जाता है कि शांति और सुख किसी बाजार में नहीं मिलते। यही वजह है कि बाहरी रूप से सफल दिखने वाला इंसान भी भीतर से तनाव और डर में जी रहा है। यह स्थिति सूफी संत की भाषा में जीवित दोज़ख़ के समान है।

दूसरी ओर, जो लोग संतुलन और सादगी को अपनाते हैं, वे सीमित साधनों में भी संतोष का अनुभव करते हैं। वे जानते हैं कि जरूरत और लालच में फर्क होता है। उनकी खुशी दूसरों से तुलना पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिति पर निर्भर होती है। ऐसे लोग कठिन समय में भी टूटते नहीं, क्योंकि उनका आधार बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता होती है। यही वह अवस्था है, जिसे सूफी दर्शन जन्नत के समान मानता है।

सूफी संतों ने हमेशा इंसानियत को धर्म से ऊपर रखा। उनके लिए सच्चा ईश्वर-भजन वही है, जिसमें इंसान इंसान के काम आए। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी के आंसू पोंछना, किसी कमजोर का सहारा बनना—यही उनके अनुसार सबसे बड़ी इबादत है। ऐसा जीवन न केवल समाज में प्रेम और सौहार्द फैलाता है, बल्कि स्वयं व्यक्ति के मन को भी हल्का और शांत करता है।

आज जब दुनिया में हिंसा, असहिष्णुता और स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, तब यह कथा हमें आत्ममंथन के लिए मजबूर करती है। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे कर्म किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम इच्छाओं के पीछे भागते-भागते रिश्तों और संवेदनाओं को खो रहे हैं? या फिर हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं, जिसमें मेहनत, प्रेम और करुणा का संतुलन बना हुआ है?

स्वर्ग और नरक किसी अदृश्य अदालत के फैसले नहीं हैं। वे हमारे रोज़मर्रा के चुनावों से बनते हैं। हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, वैसा ही संसार हमारे सामने खड़ा हो जाता है। यदि मन में क्रोध और घृणा है, तो दुनिया शत्रु जैसी लगेगी। यदि मन में प्रेम और करुणा है, तो वही दुनिया सुंदर और अपनापन देने वाली बन जाएगी।

अंततः यह समझना जरूरी है कि जन्नत और दोज़ख़ किसी भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करते। वे यहीं, इसी पल मौजूद हैं। हर दिन हमें यह तय करना होता है कि हम अपने कर्मों से क्या रच रहे हैं—स्वर्ग या नरक। सूफी संत की यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है कि सच्ची जन्नत दूसरों के जीवन में खुशियां भरने में है और सच्चा दोज़ख़ दूसरों को पीड़ा देने में। जो इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके लिए यह धरती ही स्वर्ग बन जाती है।

भारत ने बिछाई बड़ी कूटनीतिक बिसात तो
सौदेबाजी की मेज पर भागता हुआ आया अमेरिका

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अमेरिका यात्रा ऐसे समय हो रही है जब वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा और व्यापारिक खींचतान एक दूसरे में उलझ चुकी हैं। जयशंकर की यह यात्रा आपूर्ति श्रृंखला, दुर्लभ खनिज, रक्षा सहयोग और व्यापार समझौते पर नए संतुलन की तलाश है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की पहल पर आयोजित महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में जयशंकर की भागीदारी इस बात का संकेत है कि आने वाले दशक की शक्ति राजनीति खनिज, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा के इर्द गिर्द घूमेगी।इस यात्रा का पहला स्पष्ट लक्ष्य महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब यह समझ चुकी हैं कि दुर्लभ खनिजों पर निर्भरता केवल आर्थिक विषय नहीं बल्कि सामरिक प्रश्न है। चीन जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता कम करने की मुहिम में भारत को एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। भारत की खनिज क्षमता, विशाल बाजार और तकनीकी मांग उसे इस खेल का केन्द्रीय खिलाड़ी बनाती है।

जयशंकर की यह यात्रा सात महीने बाद उनकी पहली द्विपक्षीय अमेरिका यात्रा है। पिछली यात्रा उस समय हुई थी जब अमेरिका ने भारत पर कड़े शुल्क नहीं लगाए थे। इन महीनों में बहुत कुछ बदल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद शुल्क को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क और रूस से तेल खरीद पर दंडात्मक शुल्क ने संबंधों में कड़वाहट घोली। अब संकेत मिल रहे हैं कि वाशिंगटन नरमी दिखा सकता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि रूस से तेल खरीद घटने पर अतिरिक्त शुल्क हटाने का रास्ता है। साथ ही वेनेजुएला से तेल खरीद फिर शुरू करने की अनुमति का संदेश भी दिया गया है। यह सब केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि वार्ता की मेज पर सौदेबाजी के पत्ते हैं।

दिलचस्प यह है कि इसी बीच भारत ने 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता पूरा कर लिया। इसने अमेरिका को यह संदेश दिया कि नई दिल्ली विकल्प तलाशने में सक्षम है। अटलांटिक परिषद से जुड़े विशेषज्ञ मार्क लिंस्काट का आकलन है कि भारत यूरोप समझौता अमेरिका भारत व्यापार वार्ता को तेज कर सकता है। साफ है कि वाशिंगटन भारत को खोना नहीं चाहता। वैसे भी भारत और अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व की हालिया बातचीत और सार्वजनिक बयानों से यह आभास भी मजबूत हो रहा है कि दोनों देश लंबित व्यापार समझौते को अब अधिक देर तक टालना नहीं चाहते। पिछले महीनों में फोन पर हुई वार्ताओं, मंत्रिस्तरीय संपर्क और समान हितों पर दिए गए जोर से यह संकेत मिलते हैं कि माहौल को जानबूझकर सकारात्मक बनाया जा रहा है। ऐसे में जयशंकर की अमेरिका यात्रा को केवल खनिज या सामरिक चर्चा तक सीमित नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे संभावित व्यापार समझौते की राह साफ करने वाली पहल के रूप में भी समझा जा रहा है। कूटनीतिक गलियारों में यह धारणा बन रही है कि यदि इस यात्रा में मुख्य अड़चनों पर सहमति का रास्ता निकलता है तो यह आगे की औपचारिक वार्ता के लिए हरी झंडी जैसा होगा, जिसके बाद मोदी सरकार अंतिम राजनीतिक स्वीकृति देकर समझौते पर मुहर लगा सकती है। यानी यह दौरा भविष्य के बड़े आर्थिक फैसले की भूमिका भी लिख सकता है।

हम आपको यह भी बता दें कि अपनी यात्रा से पहले जयशंकर ने भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। उनके साथ अमेरिकी संसद के सदस्य जिमी पैट्रोनिस, माइक रोजर्स और एडम स्मिथ भी मौजूद रहे। बातचीत में व्यापार, रक्षा सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज, हिंद प्रशांत क्षेत्र और यूक्रेन संघर्ष जैसे विषय शामिल रहे। यह केवल शिष्टाचार भेंट नहीं बल्कि जमीन तैयार करने वाली बातचीत थी। गोर ने भारत को अमेरिका का अहम भागीदार बताया और साझा सामरिक हितों पर जोर दिया। साथ ही अमेरिकी संसदीय दल की जनवरी में नई दिल्ली यात्रा भी रक्षा तकनीक सहयोग, सह उत्पादन और सह विकास पर केंद्रित रही। संदेश साफ है कि रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग संबंधों की रीढ़ बन सकता है।

अब इस पूरे घटनाक्रम को भारत के केंद्रीय बजट की घोषणाओं से जोड़कर देखिये। मोदी सरकार ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज संपन्न राज्यों में दुर्लभ खनिज गलियारे बनाने का प्रस्ताव रखा है। खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और निर्माण को बढ़ावा देने की योजना सीधे उसी दिशा में जाती है जिस पर अमेरिका और उसके सहयोगी काम कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर अभियान के लिए ये खनिज अनिवार्य हैं। बैटरी भंडारण के लिए लिथियम आयन कोश निर्माण, सौर कांच के लिए सोडियम एंटिमोनेट, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आयातित सामान पर मूल शुल्क छूट, मिश्रित सीएनजी पर उत्पाद शुल्क गणना से जैव गैस को बाहर रखना और बैटरी भंडारण परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर सहायता को पांच गुना बढ़ाना दिखाता है कि भारत ऊर्जा और प्रौद्योगिकी की नई दौड़ के लिए तैयारी कर रहा है। 2030 तक पांच सौ गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा और 2047 तक सौ गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य भारत की नई सामरिक दिशा है। निजी भागीदारी खोलने वाला परमाणु ऊर्जा कानून भी इसी कड़ी का हिस्सा है।

सच यह है कि दुनिया नए शीत युद्ध जैसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां गोलियों से ज्यादा खनिज, चिप और ऊर्जा की आपूर्ति श्रृंखला ताकत तय करेगी। जयशंकर की यात्रा को केवल कूटनीतिक दौरा समझना भूल होगी। यह भारत की बहुस्तरीय चाल है। एक ओर अमेरिका से तनाव घटाना, दूसरी ओर अपने हितों पर अडिग रहना, और साथ साथ यूरोप, रूस तथा अन्य साझेदारों के साथ संतुलन बनाए रखना आसान नहीं। पर भारत अब रक्षात्मक नहीं, सौदेबाज की मुद्रा में दिख रहा है।

अभियान

महादेव की महाकृपा से बिहार की धरती पर अवतरित हुआ आस्था का विराट स्वरूप

भारतवर्ष की सनातन परंपरा में कुछ क्षण ऐसे होते हैं, जो केवल एक घटना नहीं रहते, बल्कि युगों तक स्मृति, श्रद्धा और चेतना में जीवित रहते हैं। 17 जनवरी 2026 का दिन भी ऐसा ही एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण बनकर उभरा है। बिहार की पावन भूमि पर, चकिया–केसरिया पथ स्थित कैथवलिया में निर्मित विराट रामायण मंदिर परिसर में विश्व के सबसे विशाल शिवलिंग की स्थापना ने पूरे देश को भक्ति, गौरव और दिव्यता से भर दिया है। यह केवल पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, तप, साधना और विश्वास का साकार रूप है।

सनातन धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा गया है। वे सृष्टि के संहारक भी हैं और करुणा के सागर भी। उनके लिए न राजसी वैभव चाहिए, न दिखावटी पूजा। एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में जब बिहार की धरती पर 210 टन वजनी, 33 फीट ऊंचा और 33 फीट चौड़ा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित हुआ, तो यह स्पष्ट हो गया कि यह आयोजन केवल भौतिक विराटता का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना के उत्कर्ष का प्रतीक है। 17 जनवरी 2026 को माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। यह तिथि स्वयं में अत्यंत पवित्र मानी जाती है, क्योंकि प्रत्येक माह की कृष्ण चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि भगवान शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है, जब चेतना और ऊर्जा एक होकर सृष्टि को संतुलन प्रदान करती हैं। ज्योतिषियों के अनुसार, इसी पावन तिथि पर शिवलिंग की स्थापना होना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। यह तिथि साधना, तप और आत्मशुद्धि के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है।

इस ऐतिहासिक दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह मकर संक्रांति के ठीक बाद आया। मकर संक्रांति वह काल है, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। यह प्रकाश, ऊर्जा और सकारात्मकता की वृद्धि का समय होता है। मान्यता है कि इस काल में किए गए धार्मिक कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसी उत्तरायण काल में, माघ कृष्ण चतुर्दशी को, मूल और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के शुभ संयोग में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होना, इसे एक अद्भुत दिव्य आयोजन बना देता है।

विराट रामायण मंदिर में स्थापित यह शिवलिंग अपने आप में कई विशिष्टताओं को समेटे हुए है। 33 फीट ऊंचाई और 33 फीट चौड़ाई का यह शिवलिंग केवल आकार में ही नहीं, बल्कि अपनी रचना में भी अद्वितीय है। इसमें 1008 छोटे शिवलिंग समाहित किए गए हैं, जो सहस्र नामों और सहस्र रूपों में भगवान शिव की उपासना का प्रतीक हैं। शिवलिंग का आधार पीठ प्रारंभ में 36 फीट लंबा है, जो स्थापना के बाद 56 फीट का भव्य स्वरूप धारण करेगा। केवल आधार पीठ को तैयार करने में ही लगभग दो वर्षों का समय लगा, जो इस परियोजना की गंभीरता और साधना को दर्शाता है।

इस दिव्य शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुआ, जो स्वयं शिल्पकला और मंदिर निर्माण की विश्वविख्यात भूमि है। वहां के कुशल शिल्पकारों ने अपनी पीढ़ियों की साधना, अनुभव और भक्ति को इस शिवलिंग में उतार दिया। 47 दिनों की लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद यह शिवलिंग बिहार के कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर पहुंचा। इस यात्रा के दौरान जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा, भजन-कीर्तन और आरती से शिवलिंग का स्वागत किया, मानो स्वयं महादेव अपने भक्तों के बीच भ्रमण कर रहे हों। शिवलिंग की स्थापना से पहले और बाद में विराट रामायण मंदिर परिसर पूरी तरह भक्ति में डूब गया। हजारों श्रद्धालु दूर-दूर से यहां पहुंचे। "हर हर महादेव", "बोल बम" और "ॐ नमः शिवाय" के जयघोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। भव्य अभिषेक की तैयारियां की गईं, जिसमें जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल और पंचामृत से महादेव का अभिषेक किया गया। यह दृश्य ऐसा था, जिसे देखने मात्र से मन शुद्ध और शांत हो जाए।

सनातन परंपरा में शिवलिंग को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना गया है। शिवलिंग न तो केवल एक मूर्ति है और न ही केवल एक प्रतीक, बल्कि यह निराकार और साकार के बीच की वह कड़ी है, जहां से सृष्टि की ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब कोई श्रद्धालु शिवलिंग के सामने ध्यान करता है, तो वह स्वयं को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ अनुभव करता है। ऐसे में इतने विराट शिवलिंग की स्थापना का अर्थ है कि यहां साधना करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव से गुजरेगा।

विराट रामायण मंदिर पहले से ही आस्था का बड़ा केंद्र माना जा रहा है। अब इस विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना के बाद यह स्थल केवल बिहार या भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के शिवभक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ के रूप में उभरेगा। यह मंदिर राम और शिव—दोनों की चेतना को एक साथ समेटे हुए है। राम मर्यादा और धर्म के प्रतीक हैं, जबकि शिव वैराग्य और करुणा के। जब ये दोनों तत्व एक ही स्थान पर प्रतिष्ठित होते हैं, तो वह भूमि स्वयं तीर्थ बन जाती है।

भक्ति की दृष्टि से देखें तो यह आयोजन हमें यह भी सिखाता है कि आस्था केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं है। जब समाज, शिल्पकार, साधु-संत, श्रद्धालु और साधारण जन मिलकर एक दिव्य उद्देश्य के लिए एकत्र होते हैं, तब एक ऐसा कार्य साकार होता है, जो पीढ़ियों तक प्रेरणा देता है। यह शिवलिंग आने वाले समय में न केवल एक धार्मिक धरोहर होगा, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का भी केंद्र बनेगा। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे भाव के भूखे हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी इसी भाव का प्रतीक है। इसकी विराटता हमें यह नहीं सिखाती कि ईश्वर को भव्यता चाहिए, बल्कि यह बताती है कि जब श्रद्धा विशाल होती है, तो उसका स्वरूप भी विराट हो जाता है। बिहार की धरती पर यह शिवलिंग इस बात का प्रमाण है कि भक्ति और आस्था आज भी जीवित हैं, और जब वे एक दिशा में प्रवाहित होती हैं, तो इतिहास रचती हैं।

अंततः यह कहा जा सकता है कि 17 जनवरी 2026 केवल एक तिथि नहीं, बल्कि सनातन चेतना के नव जागरण का दिन है। विराट रामायण मंदिर में स्थापित विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देता रहेगा कि महादेव केवल कैलाश पर ही नहीं, बल्कि उस हर हृदय में निवास करते हैं, जहां श्रद्धा, समर्पण और प्रेम है। जो भी भक्त यहां आएगा, वह केवल शिवलिंग के दर्शन नहीं करेगा, बल्कि अपने भीतर बसे शिव को भी अनुभव करेगा। हर हर महादेव।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

बिट्स पिलानी गोवा कैंपस में 20 वर्षीय छात्रा की आत्महत्या परिसर में चिंता और छात्रों के बीच डर का माहौल

(जीएनएस)। पणजी। गोवा के वास्को में स्थित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान बिट्स पिलानी के गोवा कैंपस से रविवार देर रात बेहद दुखद और चिंताजनक खबर आई है। संस्थान के हॉस्टल में तीसरे वर्ष की छात्रा वैष्णवी जितेश ने कथित तौर पर फांसी लगाकर अपने जीवन का अंत कर लिया। 20 वर्षीय वैष्णवी मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वाली थी और बिट्स पिलानी में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। इस घटना ने न केवल छात्र समुदाय में भय और शोक का माहौल पैदा किया है, बल्कि उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की मानसिक स्थिति और सुरक्षा के प्रति गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रविवार रात करीब 11:30 बजे वेर्णा पुलिस को सूचना मिली कि छात्रा अपने हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली। जब पुलिस और हॉस्टल स्टाफ मौके पर पहुंचे, तो कमरे में शव को देखकर सभी स्तब्ध रह गए। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस हर पहलू की छानबीन कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और छात्रा के दोस्तों, सहपाठियों और हॉस्टल स्टाफ से पूछताछ जारी है। यह घटना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि पिछले दो वर्षों के भीतर यह कैंपस में छठी आत्महत्या है। इन घटनाओं ने छात्र समुदाय और अभिभावकों के बीच चिंता और भय का माहौल पैदा कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार

इस तरह की घटनाएं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, परीक्षा और अकादमिक दबाव, सामाजिक अलगाव और समर्थन की कमी को उजागर करती हैं। छात्र जीवन में मिलने वाली चुनौतियाँ केवल शैक्षणिक नहीं होतीं, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक दबाव भी गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।

गोवा राज्य विधानसभा में भी हाल ही में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने बिट्स पिलानी में छात्रों की लगातार बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस दौरान स्वीकार किया कि परीक्षा और अकादमिक दबाव छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं और कई छात्र इसी कारण घातक कदम उठा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य प्रशासन इस मामले पर निगरानी रखेगा, लेकिन इस दिशा में अभी तक ठोस कदमों की कमी देखने को मिल रही है।

वर्तमान घटना ने संस्थान के प्रशासन और शिक्षा मंत्रालय के सामने कई चुनौतीपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके लिए उपलब्ध काउंसलिंग सुविधाओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी चुनौती यह है कि छात्रों को परीक्षा, असाइनमेंट और समयसीमा के दबाव से निपटने के लिए ठोस मार्गदर्शन और सामाजिक समर्थन उपलब्ध कराया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि छात्र जीवन में अकेलापन, प्रतिस्पर्धा और भावनात्मक दबाव इस तरह की आत्मघाती प्रवृत्तियों को जन्म दे सकते हैं।

हालांकि बिट्स पिलानी प्रशासन की ओर से इस घटना पर अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन छात्रों और अभिभावकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। छात्र संघ और छात्र कल्याण समितियों ने कहा है कि यह संस्थान और प्रशासन के लिए चेतावनी है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुदृढ़ता और हॉस्टल में सुरक्षा उपायों को बढ़ाना अनिवार्य है। विशेषज्ञों का कहना है कि संस्थान को नियमित रूप से मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाएँ आयोजित करनी चाहिए, छात्रों के तनाव को समझने और कम करने के लिए काउंसलिंग और परामर्श उपलब्ध कराना चाहिए।

इस दुखद घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल अकादमिक सफलता पर जोर देने से छात्रों की समग्र भलाई सुनिश्चित नहीं हो सकती। मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, और भावनात्मक समर्थन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों को प्रतिस्पर्धा के दबाव में अकेला छोड़ना भविष्य में और गंभीर घटनाओं को जन्म दे सकता है।

गोवा में बिट्स पिलानी कैंपस में लगातार हो रही आत्महत्या की घटनाओं ने शिक्षा संस्थानों और राज्य प्रशासन दोनों के सामने एक गंभीर चुनौती पेश कर दी है। प्रशासन, शिक्षकों और अभिभावकों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र न केवल शैक्षणिक रूप से सक्षम हों, बल्कि मानसिक रूप से भी सुरक्षित और समर्थ हों। इस दिशा में त्वरित और ठोस कदम उठाना न केवल संस्थान की जिम्मेदारी है, बल्कि राज्य और देश के शिक्षा ढांचे की मजबूती के लिए भी अनिवार्य है।

वैष्णवी जितेश की यह दुखद घटना न केवल बिट्स पिलानी बल्कि पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र में छात्रों की भलाई और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी पर गहरी चिंता पैदा कर रही है। विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए हर संस्थान को अपने छात्रों के लिए काउंसलिंग, समर्थन और सुरक्षा के ठोस उपाय करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। यह मामला शिक्षा संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य, छात्र सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारी की दिशा में एक चेतावनी बन चुका है।

पश्चिम रेलवे का 70वाँ रेल सप्ताह समारोह

महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार द्वारा 92 कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 'विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार' (VRSP) से सम्मानित किया गया

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के 70वें रेल सप्ताह समारोह के अंतर्गत विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार (VRSP) 2025 का आयोजन सोमवार, 02 फरवरी, 2026 को यशवंतराव चव्हाण सभागार, मुंबई में किया गया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (प्रभारी) श्री प्रदीप कुमार ने पश्चिम रेलवे के 92 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार (VRSP) प्रदान किए।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य पश्चिम रेलवे के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता को सम्मानित करना होता है, जो सदैव चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे सक्षम एवं कर्मठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से चयनित कर्मियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार न केवल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि अन्य कर्मचारियों को भी आगामी वर्ष में और अधिक उत्साह एवं समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।

इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO) की अध्यक्षा श्रीमती ईशा मलिक, प्रमुख विभागाध्यक्ष, मंडल रेल प्रबंधक, मुख्य कारखाना प्रबंधक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (प्रभारी) श्री प्रदीप कुमार ने सभी पुरस्कार विजेताओं को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों एवं संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में दिए गए योगदान के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम रेलवे अपने सभी कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों के कारण अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कर सका है। श्री प्रदीप कुमार ने पश्चिम रेलवे की हाल की विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कर्मचारियों से रेलवे तथा राष्ट्र की समग्र प्रगति के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने वर्ष के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रमुख विभागाध्यक्षों/मंडल रेल प्रबंधकों/मुख्य कारखाना प्रबंधकों को स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 'अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार' (AVRS) 2025 के उन सात व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को भी सम्मानित किया, जिन्हें हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय रेल सप्ताह समारोह के दौरान माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया था।

केन्द्रीय बजट 2026-27 में मध्य प्रदेश को 15,188 करोड़ रूपये का रेल बजट आवंटन

उच्च-गति कनेक्टिविटी, माल ढुलाई और सुरक्षा एवं यात्री सुविधाओं पर विशेष फोकस

(जीएनएस)। रतलाम 02 फरवरी। माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने प्रस्तुत बजट में भारतीय रेलवे के लिए किए गए प्रावधानों पर वीडियों कान्फ्रेंसिंग से चर्चा करते हुए बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 11 वर्षों में रेलवे के विकास के लिए अधिकाधिक बल दिया गया है जिससे रेलवे पर उच्च-गति कनेक्टिविटी, माल ढुलाई और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। केन्द्रीय बजट 2026–27 में भारतीय रेल के लिए 2,93,030 करोड़ रूपए के रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की योजना बनाई गई है। यह भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और आवंटन है। रेलवे में संरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए इस बजट में 120 हजार करोड़ रूपए का आंवटन किया गया है। माननीय रेलमंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश राज्य में रेलवे के निरंतर विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस वर्ष भी मध्य प्रदेश राज्य में रेलवे के विस्तार, सेफ्टी, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026-27 के बजट में 15,188 करोड़ रूपए आवंटन किया गया है। श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मध्य प्रदेश में रेल कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं। राज्य में 1,18,379 करोड़ रूपए की विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत न्यू ट्रैक्स प्रोजेक्ट्स पर कार्य चल रहा है। मध्य प्रदेश में 100 प्रतिशत रेल लाइनों को विद्युतीकरण हो गया है। अमृत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों को रूपये 3,163 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित किया

जा रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक पर 1283 फ्लाईओवर और रोड अण्डर ब्रिज का निर्माण किया गया है। माननीय रेलमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश में रेल परियोजनाओं को पर्याप्त बजट के माध्यम से लक्षित समय में पूरा करने की बात पर जोर दिया। संरक्षा के बारे में बताते हुए माननीय रेलमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे पर अत्यानुधिक कवच प्रणाली को विभिन्न रेलमार्गों पर स्थापित किये जाने सम्बन्धी कार्य तीव्र गति से किये जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 4591 रूट किलोमीटर रेलमार्ग पर कवच प्रणाली कार्य योजना तैयार कर ली गई है। उन्होने बताया कि कवच प्रणाली को स्थापित करने में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने, टावर लगाने, डेटा सेन्टर स्थापित करने और आरएफआईडी डिवाइस लगाने जैसे कार्य किए जाते है। यात्री सुविधाओं के विषय में माननीय रेलमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों को कवर करते हुए 5 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें एवं 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के लिए यह रेल बजट राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ-साथ यात्री सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। माननीय रेलमंत्री जी ने बताया कि माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स दक्षता की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, केन्द्रीय बजट में पश्चिम बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सूरत तक एक नए समर्पित मालवाहक कॉरिडोर का प्रस्ताव किया गया है, जो ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। 2,052 किमी लंबा यह कॉरिडोर मौजूदा पश्चिमी समर्पित मालवाहक कॉरिडोर से जुड़ेगा, जिससे पश्चिमी तट के बंदरगाहों तक माल की बिना किसी रुकावट के आवाजाही हो सकेगी। केन्द्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि यह पूर्व–पश्चिम कॉरिडोर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापार प्रवाह को सुदृढ़ करेगा, मौजूदा रेल नेटवर्क पर दबाव कम करेगा और माल ढुलाई की दक्षता बढ़ाएगा, जिससे औद्योगिक विकास और आपूर्ति श्रृंखलाओं को काफी लाभ मिलेगा।

माननीय रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह भी कहा कि उज्जैन में आगामी सिंहस्थ मेला को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे द्वारा तैयारियाँ जोर-शोर से की जा रही हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि मेला अवधि के दौरान यात्रियों एवं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी तथा रेल संचालन एवं यात्री सुविधाओं के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं। केन्द्रीय बजट 2026–27 में घोषित पहलों के साथ, भारतीय रेलवे 'विकसित भारत' के विजन के अनुरूप तेज कनेक्टिविटी, कुशल लॉजिस्टिक्स और सुदृढ़ अवसंरचना प्रदान करते हुए राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

इसके साथ ही माननीय रेलमंत्री ने बताया कि केन्द्रीय बजट 2026–27 में गुजरात राज्य को 17,366 करोड़ रुपये तथा राजस्थान राज्य को 10,288 करोड़ रुपये का रेल बजट आवंटन किया गया है। चूँकि पश्चिम रेलवे का रतलाम मंडल गुजरात एवं राजस्थान दोनों राज्यों को सीधे जोड़ता है, अतः इन दोनों राज्यों में रेल अवसंरचना, सेफ्टी एवं यात्री सुविधाओं पर होने वाले विकास कार्यों का प्रत्यक्ष लाभ रतलाम मंडल को भी मिलेगा। इससे रतलाम मंडल में रेल परियोजनाओं, परिचालन क्षमता तथा यात्री सुविधाओं के विकास को नई गति प्राप्त होगी।

केन्द्रीय बजट 2026–27 में घोषित पहलों के साथ, भारतीय रेलवे 'विकसित भारत' के विजन के अनुरूप तेज कनेक्टिविटी, कुशल लॉजिस्टिक्स और सुदृढ़ अवसंरचना प्रदान करते हुए राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

गांधीधाम–आदीपुर रेलखंड पर चौहरीकरण कार्य के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के गांधीधाम–भुज सेक्शन में गांधीधाम–आदीपुर चौहरीकरण (Quadrupling) परियोजना के अंतर्गत गांधीधाम केबिन–आदीपुर स्टेशनों के बीच कमीशनिंग से संबंधित प्रस्तावित (TWO) कार्य के कारण 04 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

अहमदाबाद मंडल के गांधीधाम–भुज सेक्शन में गांधीधाम केबिन और आदीपुर स्टेशनों के बीच चौहरीकरण (Quadrupling) कमीशनिंग का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना क्षेत्र में रेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चौहरीकरण से इस खंड की लाइन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे ट्रेनों का परिचालन अधिक सुचारु, समयनिष्ठ और सुरक्षित बनेगा। साथ ही माल एवं यात्री यातायात का बेहतर प्रबंधन संभव होगा, जिससे क्षेत्रीय व्यापार, उद्योग और यात्रियों को लाभ पहुँचेगा। अहमदाबाद मंडल द्वारा परियोजना को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह पहल भारतीय रेल की आधुनिक, तेज़ और विश्वसनीय रेल सेवाएँ प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

पूर्णतः रद्द ट्रेनें

- 1.ट्रेन संख्या 19405/19406 पालनपुर-गांधीधाम–पालनपुर एक्सप्रेस 05 से 13 फरवरी 2026 तक निरस्त रहेगी।
- 2.ट्रेन संख्या 12966 भुज–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 06 फरवरी 2026 को निरस्त रहेगी।
- 3.ट्रेन संख्या 12965 बांद्रा टर्मिनस–भुज एक्सप्रेस 10 फरवरी 2026 को निरस्त रहेगी।
- 4.ट्रेन संख्या 12959 बांद्रा टर्मिनस–भुज एक्सप्रेस 07 फरवरी 2026 को निरस्त रहेगी।
- 5.ट्रेन संख्या 12960 भुज–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 09 फरवरी 2026 को निरस्त रहेगी।
- 6.ट्रेन संख्या 09415/09416 बांद्रा टर्मिनस-गांधीधाम–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 12 फरवरी 2026 को निरस्त रहेगी।
- 7.ट्रेन संख्या 22952 गांधीधाम–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 12 फरवरी 2026 को निरस्त रहेगी।
- 8.ट्रेन संख्या 22951 बांद्रा टर्मिनस–गांधीधाम एक्सप्रेस 13 फरवरी 2026 को निरस्त रहेगी।
- 9.ट्रेन संख्या 09009 बांद्रा टर्मिनस–भुज स्पेशल 08 फरवरी 2026 को निरस्त रहेंगी।
- 10.ट्रेन संख्या 09010 भुज–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 09 फरवरी 2026 को निरस्त रहेंगी।
- 11.ट्रेन संख्या 09011 बांद्रा टर्मिनस–भुज स्पेशल 10 फरवरी 2026 को निरस्त रहेंगी।
- 12.ट्रेन संख्या 09012 भुज–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 11 फरवरी 2026 को निरस्त रहेंगी।

आंशिक निरस्त ट्रेनें

- 1.ट्रेन संख्या 20907 दादर-भुज सयाजी नगरी एक्सप्रेस 4,7 और 8 फरवरी 2026 को गांधीधाम और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 2.ट्रेन संख्या 20908 भुज-दादर सयाजी नगरी एक्सप्रेस 5,8 और 9 फरवरी 2026 को भुज-गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 3.ट्रेन संख्या 22955 बांद्रा टर्मिनस-भुज कच्छ एक्सप्रेस 5,6 और 9 फरवरी 2026 को गांधीधाम और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 4.ट्रेन संख्या 22956 भुज-बांद्रा टर्मिनस कच्छ एक्सप्रेस 6,7 और 10 फरवरी 2026 को भुज-गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 5.ट्रेन संख्या 14321/14311 बरेली–भुज एक्सप्रेस 4 फरवरी से 09 फरवरी 2026 तक गांधीधाम और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी तथा 10 और 11 फरवरी 2026 को सामाख्याली और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 6.ट्रेन संख्या 14322/14312 भुज–बरेली एक्सप्रेस 5 फरवरी से 10 फरवरी 2026 तक भुज-गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी तथा 11 और 12 फरवरी 2026 को भुज-सामाख्याली के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 7.ट्रेन संख्या 22903 बांद्रा टर्मिनस–भुज एसी एक्सप्रेस 4,6 और 8 फरवरी 2026 को गांधीधाम और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी तथा 11 फरवरी 2026 को अहमदाबाद और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 8.ट्रेन संख्या 16336 नागरकोइल–भुज एक्सप्रेस 10 फरवरी 2026 को अहमदाबाद और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 9.ट्रेन संख्या 22904 भुज-बांद्रा टर्मिनस एसी एक्सप्रेस 5,7 एवं 9 फरवरी 2026 को भुज और गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी तथा 12 फरवरी 2026 को भुज और अहमदाबाद के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 10.ट्रेन संख्या 94801 अहमदाबाद–भुज नमोभारत एक्सप्रेस 5 फरवरी से 10 फरवरी 2026 तक गांधीधाम और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी तथा 11 और 12 फरवरी 2026 को ध्रांगध्रा और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 11.ट्रेन संख्या 94802 भुज-अहमदाबाद नमोभारत एक्सप्रेस 6 फरवरी से 11 फरवरी 2026 तक भुज और गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी तथा 12 और 13 फरवरी 2026 को भुज और ध्रांगध्रा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 12.ट्रेन संख्या 20984 दिल्ली सराय रोहिल्ला-भुज एक्सप्रेस 4 और 7 फरवरी 2026 को गांधीधाम और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 13. ट्रेन संख्या 20983 भुज–दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस 6 और 10 फरवरी 2026 को भुज-गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 14. ट्रेन संख्या 11092 पुणे-भुज एक्सप्रेस 09 फरवरी 2026 को गांधीधाम-भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 15. ट्रेन संख्या 11091 भुज–पुणे एक्सप्रेस 11 फरवरी 2026 को भुज-गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 16. ट्रेन संख्या 22483 भगत की कोठी–गांधीधाम एक्सप्रेस 10,11 और 12 फरवरी 2026 को भीलड़ी-गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
- 17. ट्रेन संख्या 22484 गांधीधाम-भगत की कोठी एक्सप्रेस 11,12 और 13 फरवरी 2026 को गांधीधाम-भीलड़ी के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

मार्ग परिवर्तित ट्रेनें

- ट्रेन संख्या 20907 दादर-भुज सयाजी नगरी एक्सप्रेस 5,6,9 और 10 फरवरी 2026 को परिवर्तित मार्ग वाया आदिपुर-गांधीधाम केबिन-भीमासर के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन गांधीधाम स्टेशन पर नहीं जाएगी।
- ट्रेन संख्या 20908 भुज-दादर सयाजी नगरी एक्सप्रेस 6,7,10,11 और 12 फरवरी 2026 को परिवर्तित मार्ग वाया भीमासर-गांधीधाम केबिन-आदिपुर के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन गांधीधाम स्टेशन पर नहीं जाएगी।
- ट्रेन संख्या 22955 दादर-भुज सयाजी नगरी एक्सप्रेस 7,8,10 और 11 फरवरी 2026 को परिवर्तित मार्ग वाया भीमासर-गांधीधाम केबिन-आदिपुर के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन गांधीधाम स्टेशन पर नहीं जाएगी।
- ट्रेन संख्या 22956 भुज-बांद्रा टर्मिनस कच्छ एक्सप्रेस 5,8,9,11 और 12 फरवरी 2026 को परिवर्तित मार्ग वाया आदिपुर-गांधीधाम केबिन-भीमासर के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन गांधीधाम स्टेशन पर नहीं जाएगी।
- ट्रेन संख्या 20984 दिल्ली सराय रोहिल्ला-भुज एक्सप्रेस 11 फरवरी 2026 को परिवर्तित मार्ग वाया भीमासर-गांधीधाम केबिन-आदिपुर के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन गांधीधाम स्टेशन पर नहीं जाएगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त परिवर्तन को ध्यान में रखकर यात्रा करे। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

सोना-चांदी के वायदाओं में परस्पर विरुद्ध चालः सोना वायदा 4683 रुपये बढ़ा, चांदी वायदा 6148 रुपये घटा

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 257718.39 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 107360. करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 150350.31 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 37600 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 7068.12 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 93107.71 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 140000 रुपये के भाव पर खूलकर, 146900 रुपये के दिन के उच्च और 133687 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 142217 रुपये के पिछले बंद के सामने 4683 रुपये या 3.29 फीसदी की मजबूती के साथ 146900 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 3224 रुपये या 2.7 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 122801 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 401 रुपये या 2.67 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 15414 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी फरवरी वायदा 139868 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 146500 रुपये और नीचे में 129685 रुपये पर पहुंचकर, 3590 रुपये या 2.52 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 146100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 147688 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 149900 रुपये और नीचे में 134397 रुपये पर पहुंचकर, 147688 रुपये के पिछले बंद के सामने 2113 रुपये या 1.43 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 149801 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 267501 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 267501 रुपये और नीचे में 225805 रुपये पर पहुंचकर, 265652 रुपये के पिछले बंद के सामने 6148 रुपये या 2.31 फीसदी औंधकर 259504 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 14844 रुपये या 5.23 फीसदी की गिरावट के साथ 269200 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 12328 रुपये या 4.38 फीसदी गिरकर 268951 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

मेटल वर्ग में 10209.07 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 14.75 रुपये या 1.2 फीसदी बढ़कर 1244.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 7.6 रुपये या 2.38 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 327.15 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 6.6 रुपये या 2.14 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 315 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 50 पैसे या 0.26 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 191.45 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3537.60 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5961 रुपये के भाव पर खूलकर, 5961 रुपये के दिन के उच्च और 5622 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 321 रुपये या 5.37 फीसदी की गिरावट के साथ 5659 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 322 रुपये या 5.38 फीसदी औंधकर 5658 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा 388.7 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 388.7 रुपये और नीचे में 328.5 रुपये पर पहुंचकर, 404.8 रुपये के पिछले बंद के सामने 72.5 रुपये या 17.91 फीसदी औंधकर 332.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 72.4 रुपये या 17.88 फीसदी औंधकर 332.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

क्रूड ऑयल वायदा में 321 रुपये की गिरावटः कमोडिटी वायदाओं में 107360. करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 150350.31 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवरः सोना–चांदी के वायदाओं में 93107.71 करोड़ रुपये का हुआ कारोबारः बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 37600 पॉइंट के स्तर पर

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 980 रुपये पर खूलकर, 3.8 रुपये या 0.39 फीसदी बढ़कर 982 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 58844.84 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 34262.87 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 8793.56 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 708.70 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 65.81 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 629.92 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 1301.56 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2221.13 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 3.17 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 10278 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 88605 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 26379 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 353252 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 40544 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 9856 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 22924 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 66525 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17539 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 15656 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 36147 पॉइंट पर खूलकर, 37600 के उच्च और 34994 के नीचले स्तर को छूकर, 854 पॉइंट घटकर 37600 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 203 रुपये की गिरावट के साथ 225.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 37.05 रुपये की गिरावट के साथ 17.6 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 2455.5 रुपये की बढ़त के साथ 12355 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3880.5 रुपये की बढ़त के साथ 24562.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2 रुपये की बढ़त के साथ 56 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 357.5 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 59 पैसे के सुधार के साथ 1.81 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 94.4 रुपये की बढ़त के साथ 255 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 11.7 रुपये की बढ़त के साथ 17.15 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 198.5 रुपये की बढ़त के साथ 7654.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 284 रुपये की गिरावट के साथ 10399.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 6.49 रुपये की गिरावट के साथ 52.63 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 297.5 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.67 रुपये की गिरावट के साथ 3.18 रुपये हुआ।

जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का रहस्य: 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली, संपत्ति और पोस्टमार्टम जांच ने बढ़ाई उलझन

(जीएनएस)। जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले में कथावाचक और सामाजिक कार्यकर्ता साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की जांच अब पांच दिन से जारी है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट निष्कर्ष सामने नहीं आया है। साध्वी के अचानक निधन ने न केवल उनके अनुयायियों को हक्का-बक्का कर दिया है, बल्कि पुलिस और एसआईटी टीम के लिए भी इस मामले को सुलझाना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। साध्वी प्रेम बाईसा के आश्रम और उसके आसपास के क्षेत्रों की जांच के दौरान पुलिस ने कई अहम सुराग जुटाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उनकी मौत के कारण को लेकर कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है। पुलिस और एसआईटी की जांच में साध्वी के पिता विरमनाथ और ड्राइवर को बार-बार सवालों के घेरे में लाया गया। बताया जा रहा है कि जांच टीम ने आश्रम में तीन घंटे तक पूछताछ की और बाद में शाम को विरमनाथ को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाया गया। इस दौरान पुलिस ने जांच के कई पहलुओं पर ध्यान दिया, जिनमें साध्वी के स्वास्थ्य की स्थिति, उनके अंतिम दिनों के व्यवहार और आस-पास के लोगों से मिली जानकारी शामिल है। इस बीच, ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि साध्वी के गले में खाना फंसने की वजह से उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही थी, जबकि विरमनाथ ने यह दावा किया कि उन्हें इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद सांस लेने में कठिनाई हुई।

साध्वी की संपत्ति और वित्तीय स्थिति भी जांच का केंद्र बनी हुई है। पुलिस ने उनके बैंक खातों और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया है। बताया जा रहा है कि साध्वी प्रेम बाईसा के पास 20 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति थी।

इसके साथ ही साध्वी के सोशल मीडिया अकाउंट और उनसे जुड़े सेवादारों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि संपत्ति और वित्तीय रिकॉर्ड से कई सुराग मिल सकते हैं, जो मामले को सुलझाने में मददगार हो सकते हैं।

पांच दिन से चल रही जांच के बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिए हैं। रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिससे पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं। विशेषज्ञ और पुलिस अधिकारी मान रहे हैं कि एफएसएल और विसरा की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल सकेगा। वहीं, पुलिस अब विभिन्न थ्योरीज पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सिद्धांत सामने नहीं आया है।

एसआईटी और पुलिस की जांच में आश्रम के कर्मचारियों, परिवारजनों और आस-पास के लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। बीते दो दिन से पुलिस ने आश्रम में मौजूद लोगों से लंबी पूछताछ की, जिसमें सेवादारों, मामा सुरेश और अन्य सहयोगियों से कई घंटे तक सवाल-जवाब किए गए। इन पूछताछों का उद्देश्य साध्वी की मौत के पीछे की गुत्थी को सुलझाना है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मामलों में कई पहलू होते हैं—स्वास्थ्य, व्यक्तिगत जीवन, वित्तीय लेन-देन और सामाजिक प्रभाव। साध्वी प्रेम बाईसा का सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में प्रभाव बड़ा था, इसलिए उनके आसपास के लोग और सेवादार भी जांच के दायरे में हैं। पुलिस का ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि जांच निष्पक्ष और व्यापक हो और किसी भी महत्वपूर्ण सुराग को नजरअंदाज न किया जाए।

पांचवें दिन भी पुलिस के हाथ खाली होने से जोधपुर में इस मामले ने रहस्य और संवेदनशीलता की नई परत जोड़ दी है। प्रशासन और पुलिस अधिकारी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एफएसएल और विसरा रिपोर्ट के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। इस बीच, साध्वी प्रेम बाईसा के अनुयायी और समाज के लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मौत का सच कब सामने आएगा।

इस मामले में अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है और पुलिस किसी भी थ्योरी को पकड़ने में असमर्थ रही है। एफएसएल और विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस यह तय कर सकेगी कि साध्वी की मौत प्राकृतिक थी, आकस्मिक थी या फिर इसमें कोई गम्भीर संदिग्ध गतिविधि शामिल थी। साध्वी प्रेम बाईसा की अचानक और रहस्यमय मौत ने न केवल उनके अनुयायियों को स्तब्ध कर दिया है, बल्कि जोधपुर पुलिस के सामने भी जांच की सबसे बड़ी चुनौती रख दी है।

रांची में आर्थिक तंगी और पारिवारिक तनाव ने लिया भयानक रूप: बेटे की मौत, मां और बेटी गंभीर, एक ही परिवार में उठे आत्मघाती कदम ने हिला दी कॉलोनी

(जीएनएस)। रांची। झारखंड की राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में स्थित कडरू न्यू एजी कॉलोनी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। एक ही परिवार के तीन लोगों ने अपने जीवन को खत्म करने का खौफनाक कदम उठाया। इस घटना में परिवार का बेटा मिहिर फांसी लगाकर मृत हो गया, जबकि उसकी मां स्नेहा अखौरी और 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बहन ने अत्यधिक मात्रा में दवाओं का सेवन किया, जिसके कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और दोनों को रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस आत्मघाती कदम के पीछे पारिवारिक और आर्थिक तनाव मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। मिहिर, जो कोलकाता से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करके लौट चुका था, रांची में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। मिहिर के परिवार के अनुसार वह कुछ दिन पहले ही रांची आया था। उसकी मां स्नेहा अखौरी पेशे से अधिवक्ता हैं और झारखंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती थीं, हालांकि पिछले कुछ समय से वह प्रैक्टिस नहीं कर रही थीं। परिवार की

बेटी भी पढ़ाई में अग्रणी थी, लेकिन इस तनावपूर्ण माहौल में वह भी मानसिक रूप से प्रभावित हो गई थी।

पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य एकत्र किए। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिला कि आर्थिक परेशानियों और पारिवारिक तनाव ने परिवार के मनोबल को कमजोर कर दिया था, जिससे इस खौफनाक निर्णय की ओर धकेल दिया गया। मिहिर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जबकि मां और बेटी के स्वस्थ होने के बाद उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी।

स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरे इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। पड़ोसी और कॉलोनी के लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि आखिरकार एक उच्च शिक्षित परिवार और पेशेवर माता-पिता के बीच ऐसा कदम क्यों उठाया गया। यह घटना मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक संघर्ष के प्रति समाज में चेतना बढ़ाने की भी चुनौती पेश करती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि पारिवारिक और वित्तीय तनाव, अकेलापन और सामाजिक दबाव अक्सर लोगों को आत्मघाती कदमों की ओर धकेल सकते हैं। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के लिए चेतावनी का काम किया है कि परिवारों की मानसिक स्थिति पर ध्यान दिया जाए और समय पर मदद उपलब्ध कराई जाए।

अरगोड़ा थाना के अधिकारियों ने पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने क्षेत्र में रहने वाले लोगों और परिवार के परिचितों से भी पूछताछ शुरू कर दी है ताकि यह समझा जा सके कि इस आत्मघाती कदम के पीछे और कौन-कौन से कारक जिम्मेदार थे। इसके साथ ही फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (एफएसएल) की टीम भी साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है, जिससे पता लगाया जा सके कि घटना में कोई और गम्भीर पहलू तो नहीं है।

इस घटना ने न केवल रांची बल्कि पूरे झारखंड के लिए चेतावनी का काम किया है। यह याद दिलाती है कि आर्थिक और पारिवारिक परेशानियों को हल्के में लेना जानलेवा हो सकता है। मिहिर की मौत और मां-बेटी की गंभीर स्थिति पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है और इसे मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक समर्थन और सामाजिक सुरक्षा के नजरिए से गंभीरता से देखा जाना चाहिए।

बिहार की अर्थव्यवस्था ने लगाई रफ्तार, विकास दर राष्ट्रीय औसत से आगे, प्रति व्यक्ति आय और राजस्व में बड़ा उछाल

(जीएनएस)। पटना। बिहार की अर्थव्यवस्था ने हालिया वर्षों में अभूतपूर्व तेजी दिखाई है और 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण ने इसे औपचारिक रूप से पुष्टि दे दी है। सोमवार को वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसमें राज्य की विकास दर राष्ट्रीय औसत से 3.3 प्रतिशत अधिक दर्ज की गई है। यह आंकड़ा न केवल बिहार के निरंतर आर्थिक विस्तार को दर्शाता है, बल्कि राज्य के विकासात्मक कार्यक्रमों और निवेश-उन्मुख नीतियों की सफलता को भी रेखांकित करता है।

सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय इस दौरान 76,490 रुपये तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य अगले पांच वर्षों में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। उन्होंने कहा कि बिजली, सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी ढांचे के विस्तार में सरकार ने विशेष ध्यान दिया है, जिससे औद्योगिक और रोजगार आधारित विकास के रास्ते भी खुल रहे हैं। बिहार की इस आर्थिक गति की तुलना देश के अन्य राज्यों से की जाए तो तमिलनाडु के बाद यह सर्वाधिक विकास दर वाले राज्यों में शामिल है। राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2024-25 में 9.92 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इसमें स्थिर मूल्यों पर 8.6 प्रतिशत और वर्तमान मूल्यों पर 13.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, यह वृद्धि राज्य में निवेश, उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्रों में हुए समेकित प्रयासों का प्रतिफल है।

राजस्व आय में भी बिहार ने बड़ी छलांग लगाई है। वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य की कुल राजस्व आय 1.28 लाख करोड़ रुपये थी, जो 2024-25 में बढ़कर 2.18 लाख करोड़ रुपये हो गई। कर संग्रह में हुई लगातार वृद्धि ने राज्य की वित्तीय आत्मनिर्भरता को और मजबूत किया है। इसके साथ ही, बजट के व्यय पैटर्न में भी सकारात्मक बदलाव दिखाई दिया है, जिसमें विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया गया है, जबकि स्थापना और प्रशासनिक खर्चों में कमी लाई गई। आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी रेखांकित किया गया कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में निवेश बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, सड़कों और बिजली की बेहतर पहुंच तथा कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार से राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में संतुलित सुधार हुआ है। सरकार ने अपने "संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार" के संकल्प के अनुरूप अगले बजट में औद्योगिक निवेश, आधारभूत ढांचे और सामाजिक विकास पर और जोर देने का आश्वासन दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती देने के लिए न केवल मौजूदा योजनाओं को विस्तारित किया जाएगा, बल्कि नई नीतियों के माध्यम से रोजगार, उत्पादन और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार की यह विकास दर उसकी आर्थिक रणनीतियों की सफलता को दर्शाती है, जिसमें सरकारी निवेश, उद्योग और कृषि क्षेत्र में सुधार तथा कर संग्रह और राजस्व वृद्धि शामिल हैं। इसके साथ ही, राज्य में व्यावसायिक और सामाजिक ढांचे के सुधार ने विकास की स्थिरता को सुनिश्चित किया है। आर्थिक सर्वेक्षण की यह रिपोर्ट न केवल बिहार के आर्थिक स्वास्थ्य का प्रमाण है, बल्कि यह राज्य के भविष्य की संभावनाओं और निवेश आकर्षक माहौल का भी संकेत देती है।

इस प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ते हुए विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन ने "संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार" की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए हैं।

फियो ने केंद्रीय बजट 2026–27 की सराहना की; एक मज़बूत निर्यात-सक्षम, उद्योग-अनुकूल और एमएसएमई -केंद्रित बजट के लिए सरकार को धन्यवाद: फियो अध्यक्ष, श्री एस सी रल्हन

(जीएनएस)। नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस (फियो) केंद्रीय बजट 2026–27 का गर्मजोशी से स्वागत करता है और सरकार को एक साहसिक, दूरदर्शी और सुधार-उन्मुख बजट पेश करने के लिए बधाई देता है जो भारत की विकास यात्रा को महत्वपूर्ण रूप से मज़बूत करता है, साथ ही भारतीय निर्यात, विनिर्माण और एमएसएमई की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को निर्णायक रूप से बढ़ाता है।

बजट पर टिप्पणी करते हुए, फियो के अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने माननीय वित्त मंत्री और सरकार के प्रति निरंतर आर्थिक विकास, राजकोषीय विवेक, बुनियादी ढांचे के विस्तार और विश्वास-आधारित शासन के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता के लिए अपनी सराहना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये उपाय व्यापार और निवेश इकोसिस्टम को और अधिक ऊर्जा देंगे और निर्यातकों को एक स्थिर और अनुमानित नीतिगत माहौल प्रदान करेंगे। श्री रल्हन ने कहा, "केंद्रीय बजट 2026–27 स्पष्ट रूप से भारत की आर्थिक क्षमता को ठोस प्रदर्शन में बदलने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है। विनिर्माण, एमएसएमई, बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर मज़बूत ज़ोर—सार्थक कर और सीमा शुल्क सुधारों द्वारा समर्थित—भारतीय निर्यातकों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ अधिक गहराई से और प्रतिस्पर्धी रूप से एकीकृत करने में सक्षम बनाएगा।"

फियो विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, कपड़ा, रसायन, विमान घटक, निर्माण उपकरण और दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट जैसे उच्च-मूल्य और रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को मज़बूत करने के लिए सरकार के केंद्रित दृष्टिकोण की सराहना करता है। 200 पुराने औद्योगिक समूहों के प्रस्तावित पुनरुद्धार, कई क्षेत्र-विशिष्ट पहलों के साथ, पैमाने, उत्पादकता, प्रौद्योगिकी अपनाने और निर्यात की तैयारी में सुधार की उम्मीद है। श्री रल्हन ने कहा कि उद्योग भारत के निर्यात पदचिह्न का विस्तार करने के लिए इन पहलों का सक्रिय रूप से लाभ उठाने के लिए तैयार है।

व्यापार सुविधा उपायों का स्वागत करते हुए, श्री रल्हन ने कहा कि प्रमुख इनपुट पर शुल्क छूट, निर्यात समय-सीमा का विस्तार, विश्वसनीय निर्यातकों की

पहचान और कारखाने परिसर से निर्यात कार्गो की निकासी से लेनदेन लागत में काफी कमी आएगी, व्यापार करने में आसानी में सुधार होगा और आपूर्ति-श्रृंखला दक्षता बढ़ेगी। उन्होंने कहा, "ये सुधार सीधे तौर पर निर्यातक के आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करेंगे।"

फियो अध्यक्ष ने एमएसएमई के लिए सरकार के मज़बूत और सोचे-समझे सपोर्ट की भी तारीफ़ की, जिसमें तीन तरह के तरीके अपनाए गए हैं: 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई ग्रोथ फंड, आत्मनिर्भर भारत फंड को बढ़ाना, टीआरईडी पर सीपीसीई की अनिवार्य ऑनबोर्डिंग, और इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट। श्री रल्हन ने कहा, "एमएसएमई भारत के निर्यात इकोसिस्टम की रीढ़ हैं। बजट में तरलता सहायता, इक्विटी समावेश और प्रोफेशनल कैपेसिटी-बिल्डिंग पर फोकस एमएसएमई को आगे बढ़ने, इनोवेशन करने और ग्लोबल चैंपियन बनने के लिए सशक्त करेगा।"

फियो ने सर्विस सेक्टर पर नए सिरे से ज़ोर देने का भी स्वागत किया—जिसमें आईटी, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, शिक्षा, डिज़ाइन, खेल और केयर इकोनॉमी शामिल हैं—जिसे सेफ हार्बर प्रावधानों और ज़्यादा टैक्स निश्चितता से सपोर्ट मिला है। ये उपाय, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, जलमार्गों और ऊर्जा सुरक्षा पर लगातार सार्वजनिक पूंजीगत खर्च के साथ मिलकर, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेंगे और एक वैश्विक सेवाओं और विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को और मज़बूत करेंगे।

बजट की दिशा में विश्वास व्यक्त करते हुए, श्री रल्हन ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के विज़न को प्राप्त करने के लिए एक मज़बूत नींव रखता है, जो विकास, समावेशन और राजकोषीय अनुशासन को संतुलित करता है। उन्होंने कहा "बजट वैश्विक बाजारों को एक मज़बूत और सकारात्मक संकेत भेजता है और एक विश्वसनीय, लचीले और आकर्षक व्यापार और निवेश गंतव्य के रूप में भारत की विश्वसनीयता को मज़बूत करता है। भारतीय उद्योग और निर्यातक इन पहलों के लाभों को अधिकतम करने और निर्यात-आधारित विकास में तेज़ी लाने के लिए सरकार के साथ साझेदारी करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।"

नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में प्रस्तुत गुजरात की झांकी को 'पॉपुलर चॉइस कैटेगरी' में प्रथम पुरस्कार प्राप्त

सूचना एवं प्रसारण सचिव डॉ. विक्रांत पांडे तथा सूचना आयुक्त श्री किशोर बचाणी ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को विजेता ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया

(जीएनएस)। गांधीगर : 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में प्रस्तुत की गई गुजरात की झांकी ने वर्ष 2026 में लगातार चौथे वर्ष 'पॉपुलर चॉइस श्रेणी' में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को सूचना एवं प्रसारण सचिव डॉ. विक्रांत पांडे तथा सूचना आयुक्त श्री किशोर बचाणी द्वारा सोमवार को यह विजेता ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार तथा सूचना आयुक्त कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

भारतीय रेलवे ने गुजरात में अभूतपूर्व अवसंरचना विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया

(जीएनएस)। ऐतिहासिक बजट आवंटन, आधुनिक स्टेशन और विश्वस्तरीय ट्रेन सेवाओं से बदल रहा है रेल परिदृश्य भारतीय रेलवे ने गुजरात में अभूतपूर्व बजटीय सहयोग और तीव्र अवसंरचना विकास के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है जिससे राज्य भर में सुरक्षित, आधुनिक और यात्री-केंद्रित रेल परिवहन के एक नए युग की शुरुआत हुई है। गुजरात के लिए रेलवे का औसत वार्षिक बजट आवंटन वर्ष 2009–14 के दौरान 589 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2026–27 की अवधि में 17,366 करोड़ हो गया है। यह लगभग 29 गुना वृद्धि है, जो राज्य में रेल अवसंरचना और संपर्क सुदृढ़ करने के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

बड़े पैमाने पर अवसंरचना विस्तार

वर्तमान में गुजरात में 1,28,748 करोड़ लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएँ प्रगति पर हैं। इन कार्यों में नई रेल लाइनों का निर्माण, स्टेशन पुनर्विकास तथा प्रमुख सुरक्षा उन्नयन शामिल हैं, जो नेटवर्क में दीर्घकालिक क्षमता वृद्धि और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करते हैं।

अमृत स्टेशन योजना: स्टेशनों का कायाकल्प

अमृत स्टेशन योजना के तहत गुजरात के 87 रेलवे स्टेशनों को 6,058 करोड़ की कुल लागत से व्यापक पुनर्विकास हेतु चिन्हित किया गया है। अब तक 19 स्टेशनों - जिनमें सामाख्याली,डाकोर, हापा, जाम जोधपुर, मोरबी, ओखा, पालीताना, पोरबंदर, सहित अन्य स्टेशन शामिल हैं का पुनर्विकास कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे यात्री सुविधाओं और स्टेशन सौंदर्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

प्रीमियम ट्रेनों से बेहतर संपर्क

आधुनिक ट्रेन सेवाओं के परिचालन से यात्री सुविधा और यात्रा दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में गुजरात में निम्न सेवाएँ संचालित हैं:

5 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस
1 जोड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस
1 जोड़ी नमो भारत एक्सप्रेस

ये सेवाएँ यात्रियों को तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा विकल्प प्रदान करती हैं।

नेटवर्क विस्तार और 100% विद्युतीकरण

वर्ष 2014 के बाद से गुजरात के रेल नेटवर्क में तीव्र विस्तार हुआ है। लगभग 2,900 किमी नई रेल लाइनों का निर्माण किया गया है, जो कई यूरोपीय देशों के कुल रेल नेटवर्क से भी अधिक है। राज्य ने 4,005 किमी रेल लाइनों के विद्युतीकरण के साथ 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है जिससे हरित और ऊर्जा-कुशल संचालन को बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त, समपार फाटकों को समाप्त करने हेतु 1,177 फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया गया है, जिससे सुरक्षा बढ़ी है और सड़क-रेल यातायात सुगम हुआ है।

कवच प्रणाली से रेल सुरक्षा सुदृढ़

सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भारतीय रेलवे गुजरात में स्वदेशी 'कवच' स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली लागू कर रहा है। अब तक 96 रूट किमी पर कवच प्रणाली स्थापित की जा चुकी है, जबकि कुल स्वीकृत 1,842 रूट किमी में से 1,674 रूट किमी पर कार्य या निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। यह रेल सुरक्षा मानकों में एक महत्वपूर्ण छलांग है।

रिकॉर्ड निवेश, आधुनिक स्टेशनों, प्रीमियम ट्रेनों, पूर्ण विद्युतीकरण और उन्नत सुरक्षा प्रणालियों के साथ भारतीय रेलवे गुजरात के अवसंरचना विकास और सामाजिक-आर्थिक प्रगति में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का राजस्व क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय

- राज्य में विभिन्न इनामी जमीनों के अवैध कब्जा अधिकार नियमित किए जाएंगे : किसानों को होगा बड़ा लाभ
- रीग्रांट की गई हो या करने योग्य होने पर भी रीग्रांट न हुई हो, ऐसी जमीन को आसानी से नियमित किया जा सकेगा

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राजस्व क्षेत्र में राज्य में विभिन्न इनामी जमीनों के अवैध कब्जा अधिकार को नियमित करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय के अनुसार रीग्रांट की गई हो या करने योग्य होने पर भी रीग्रांट नहीं हुई है, ऐसी जमीन को आसानी से नियमित किया जा सकेगा। इसके लिए जमीन की मौजूदा जंत्री दर की 20 फीसदी कब्जा अधिकार राशि जमा कर नियमित किया जा सकता है।

इस निर्णय का लाभ ऐसी जमीनों के कब्जेदारों जिनकी जमीनें रीग्रांट की गई हैं, लेकिन कब्जे की कीमत जमा नहीं की गई है तथा ऐसे उत्तराधिकारी जो उस जमीन के धारक हैं, जो रीग्रांट के योग्य है, लेकिन किसी कारण से रीग्रांट नहीं हुई हैं, को इस निर्णय का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, ऐसी हस्तांतरित की गई जमीनों के ऐसे वर्तमान कब्जेदारों को भी इस निर्णय का लाभ मिलने से राज्य के किसानों को बड़ा फायदा होगा।